



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(08 April 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार एक विशिष्ट मौलिक और मानवाधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- बोत्सवाना ने जर्मनी में 20,000 हाथियों को भेजने की धमकी दी

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ अधिकार एक विशिष्ट मौलिक और मानवाधिकार: सुप्रीम कोर्ट

मामला क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार करते हुए अब "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" को भी इसके दायरे में शामिल कर दिया है।
- कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक "मौलिक मानवाधिकार" है।



भारत का संविधान 'प्राकृतिक दुनिया' के महत्व को पहचानता है:

- एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान 'प्राकृतिक दुनिया' के महत्व को पहचानता है क्योंकि यह बात अनुच्छेद 51A का खंड (g) रेखांकित करता है जो "यह निर्धारित करता है कि जंगलों, झीलों, नदियों और



वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा"।

जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार:

- जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वच्छ, स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकारों को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि "स्वास्थ्य का अधिकार (जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है) वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, तूफान, फसल की विफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी और बाढ़ जैसे कारकों के कारण प्रभावित होता है"।
- साथ ही न्यायालय ने आगे कहा कि "वंचित समुदायों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने या इसके प्रभावों से निपटने में असमर्थता जीवन के अधिकार के साथ-साथ समानता के अधिकार (अनुच्छेद-14) का भी उल्लंघन करती है। यदि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के कारण किसी विशेष क्षेत्र में भोजन और पानी की गंभीर कमी हो जाती है, तो गरीब समुदायों को नुकसान, अमीर लोगों से भी ज्यादा होता है"।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- फैसले में कहा गया कि ऐसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक "मौलिक मानवाधिकार" है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश करने वाली सरकारी नीति और नियमों और विनियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन और संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है।
- "हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार नहीं है"।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला क्या था?

- सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) को बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के कारण अपना निवास स्थान खोने से बचाने की याचिका पर सुनवाई कर रहा थी।
- उल्लेखनीय है कि 19 अप्रैल, 2021 को, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और ओवरहेड लो और हाई-वोल्टेज लाइनों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने पर विचार किया था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050

+918988886060



www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बाद में सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया और अपने निर्देशों में संशोधन की मांग की।
- इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने तकनीकी और भूमि अधिग्रहण चुनौतियों और निषेधात्मक लागतों सहित आदेश को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा किया।
- अदालत ने "इलाके, जनसंख्या घनत्व और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता का आकलन करने" के लिए विशेषज्ञों की एक नई सदस्यीय समिति भी गठित की। इसने समिति को अपना कार्य पूरा करने और 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले केंद्र सरकार के माध्यम से अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



बोत्सवाना ने जर्मनी में 20,000 हाथियों को भेजने की धमकी दी:

चर्चा में क्यों है?

- बोत्सवाना के राष्ट्रपति मोकग्वेत्सी मसीसी ने 3 अप्रैल को 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दी। यह बयान जर्मनी द्वारा इस साल की शुरुआत में शिकार करने वाले जानवरों से ट्रॉफियों के आयात पर कड़ी सीमाएं लागू करने के प्रस्ताव के बाद आया है।
- जर्मन समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में, बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी, जो यूरोपीय संघ में शिकार ट्रॉफियों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, का ऐसा कदम उनके देश में लोगों को गरीब बना देगा।
- उन्होंने यह भी कहा कि शिकार से बोत्सवाना में हाथियों की आसमान छूती संख्या पर अंकुश लगाने में मदद मिली, जो दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी (लगभग 1.3 लाख) का घर है।
- यही कारण है कि बोत्सवाना नहीं चाहता कि जर्मन हाथियों का शिकार करना बंद करें।



ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बेल्जियम उन देशों में से हैं जिन्होंने शिकार ट्रॉफियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बोत्सवाना में इतने सारे हाथी क्यों हैं?

- बोत्सवाना, अपने पड़ोसियों के विपरीत, अपनी स्थिर सरकार और छोटी मानव आबादी के कारण हाथियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है।
- बोत्सवाना ने भी सख्त संरक्षण नीतियां लागू कीं। जब 2013 में अवैध शिकार की घटनाएं बढ़ रही थी, तो इसने संदिग्ध शिकारियों को लक्षित करने के लिए 'शूट-टू-किल' नीति की घोषणा की। अगले वर्ष, देश ने ट्रॉफी शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया - शिकार जो पहले आधिकारिक सरकारी लाइसेंस के तहत होता था।
- इन कारणों से, पिछले कुछ वर्षों में देश में हाथियों की आबादी लगातार बढ़ी है।
- पर्यावरण संरक्षण संगठन, कंजर्वेशन फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां 1960 के दशक की शुरुआत में, देश में 10,000 से भी कम हाथी थे, वहीं 1990 के दशक के मध्य तक, जनसंख्या 80,000 तक पहुंच गई थी।
- आज, बोत्सवाना की लगभग 40% भूमि पर हाथी निवास करते हैं।

बोत्सवाना के लिए हाथी एक मुद्दा क्यों बन गए हैं?

- बोत्सवाना में हाथियों की बढ़ती आबादी के कारण मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह जानवर देश के ग्रामीण समुदायों के लिए

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



खतरा बन गया है, नियमित रूप से घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, पाइपों से पानी पी रहा है, फसलों को खा रहा है या नष्ट कर रहा है, और लोगों और मवेशियों को कुचलकर मार रहा है।

- हाथियों की एक बड़ी आबादी अन्य प्रजातियों के लिए भी खतरा है, और महत्वपूर्ण जैव विविधता हानि और निवास स्थान में गिरावट का कारण बनती है - हाथी चारे के लिए पेड़ों को तोड़ देते हैं और बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं, जिससे गैर-हाथी वन्यजीवों में गिरावट हो सकती है।

क्या शिकार ही एकमात्र समाधान है?

- समस्या से निपटने के प्रयास में, बोत्सवाना ने अन्य देशों को हाथी दान में दिए हैं। पिछले साल, इसने पड़ोसी अंगोला को लगभग 8,000 हाथी दिए और 2022 में, इसने मोजाम्बिक को 500 हाथी दान में दिए। हालांकि, इस अभ्यास से वास्तव में जानवरों की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ा है।
- बोत्सवाना में एक लाख से अधिक हाथियों के साथ, गर्भनिरोधक भी एक विकल्प नहीं है।
- यही कारण है कि देश ने 2019 में ट्रॉफी शिकार पर अपना प्रतिबंध हटा दिया। बोत्सवाना ने तर्क दिया है कि यह न केवल हाथियों की संख्या को सीमित करने

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



में मदद करता है, बल्कि शिकारियों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है।

- बोत्सवाना की सरकार ने कहा कि इस प्रथा से 2021 में स्थानीय समुदायों को 5 मिलियन डॉलर मिले - और इससे भी अधिक पैसा कमाने की गुंजाइश है।
- अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया है कि विनियमित ट्रॉफी शिकार अंततः उन प्रजातियों की मदद करता है जिन्हें शिकारी लक्षित करते हैं। सरकारें संरक्षण के लिए अमीर शिकारियों के पैसे का उपयोग कर सकती हैं, और स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा कर सकती हैं, जिससे निवास स्थान के नुकसान को रोका जा सकता है और जानवरों की बेहतर सुरक्षा की जा सकती है।

हाथियों के ट्रॉफी शिकार पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए?

- उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देश और पशु अधिकार समर्थक इस प्रथा को अनैतिक मानते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जनसंख्या में गिरावट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
- इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को भी बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050

+918988886060



www.vajiraoinstitute.com

info@vajiraoinstitute.com



- अंत में, कई लोगों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय समुदायों को ट्रॉफी हंटिंग से लाभ नहीं होता है, जैसा कि विज्ञापित किया गया है।

आगे का रास्ता:

- बहरहाल, कई विशेषज्ञों का तर्क है कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं कि सही कदम हो।
- हेलसिंकी विश्वविद्यालय के संरक्षण भूगोलवेत्ता एनरिको डि मिनिन ने एनपीआर को बताया: "यदि देश ट्रॉफी शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो उन्हें हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर के राजस्व का एक वैकल्पिक स्रोत होना चाहिए... परिणामों को जाने बिना बस चीजों पर प्रतिबंध लगाना है वास्तव में प्रजातियों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा हो रही हैं"।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)